RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 022
दि. 22.10.2025, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com


## भगवान के घर हेराफेरी: गुरुवायूर मंदिर में सोने का मुकुट चांदी से बदला, ऑडिट रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले राज

**(जीएनएस)**। तिरुवनंतपुरम। केरल की धरती पर स्थित भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर को श्रद्धा और विश्वास का केंद्र माना जाता है। हजारों भक्त हर दिन यहां अपने आराध्य को नमन करने आते हैं, सोने-चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, और यह मानते हैं कि भगवान की सेवा में सब कुछ पारदर्शी और पवित्र है। लेकिन हाल ही में सामने आई एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट ने इस आस्था की नींव को झकझोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर के खजाने में वर्षों से बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा रही थी। सोने-चांदी के मुकुट, दीप, पात्र, और यहां तक कि हाथियों के दांत जैसे कीमती सामानों में गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। यह रिपोर्ट 2019-20 और 2020-21 के बीच की है और इसमें देवस्वोम बोर्ड की लापरवाही और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं।

ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मंदिर के भीतर दैनिक अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले बहुमूल्य धातु के सामानों के वजन में लगातार कमी देखी गई। सोने का मुकुट चांदी से बदल दिया गया, कई चांदी के बर्तनों का वजन महीनों के भीतर घट गया, और कुछ तो पूरी तरह से बदल दिए गए। उदाहरण के तौर पर एक चांदी का पात्र जिसका वजन 2.65 किलोग्राम था, उसकी जगह सिर्फ 750 ग्राम का पात्र लौटा दिया गया। मंदिर प्रबंधन के पास इन वस्तुओं का लेखा-जोखा रखने के लिए डबल लॉक रजिस्टर होता है, लेकिन उसकी जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड अधूरे हैं और लौटाए गए सामान का वजन कई बार चढ़ावे से काफी कम निकला।

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि गुरुवायूर देवस्वोम के पुन्नथुर कोट्टा हाथी सेंचुरी से भी 530 किलोग्राम से अधिक हाथी दांत गायब पाए गए। ऑडिट में पाया गया कि मंदिर में हाथियों की ट्रिमिंग से जो दांत निकाले गए, उनका कोई भी रिकॉर्ड वन विभाग को नहीं सौंपा गया। कानून के अनुसार, ऐसे दांतों को दस दिनों के भीतर वन विभाग को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, लेकिन न तो महाजार (जब्ती ज्ञापन) बनाया गया और न ही हैंडओवर रसीदें तैयार की गईं। अप्रैल से नवंबर 2019 के बीच जितना हाथीदांत निकला, वह सब बिना किसी दस्तावेज के मंदिर प्रशासन के पास रहा, जो अब रहस्यमय ढंग से गायब है।

इतना ही नहीं, भक्तों की ओर से चढ़ाए गए मंजादी कुरु (एक पवित्र बीज जो भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है) के 17 बोरे भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। इन बोरों को पश्चिमी मीनार में रखा गया था और 100 रुपये प्रति किलो की दर से नीलामी भी की गई थी, लेकिन खरीदार ने कभी उन्हें उठाया नहीं। कुछ महीनों बाद CCTV फुटेज में यह देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी ट्रैक्टर में वे बोरे लादकर कहीं ले गए। जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने दावा किया कि जगह की कमी के कारण बोरे पास के गोदाम में रखे गए थे, लेकिन रिकॉर्ड में उस गोदाम का कोई उल्लेख नहीं मिला।

ऑडिट रिपोर्ट ने साफ किया कि मंदिर के कीमती सामानों की गिनती और रखरखाव की प्रक्रिया में बेहद लापरवाही बरती गई है। कई मामलों में वजन घटने के बावजूद कोई जांच नहीं की गई और पुराने रिकॉर्ड को अपडेट भी नहीं किया गया। यह सब देखकर भक्तों में आक्रोश फैल गया है। जो मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है, वहीं उसकी पवित्रता पर अब प्रश्नचिह्न लग गया है।

इस पूरे मामले पर जब गुरुवायूर देवस्वोम बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष वी. के. विजयन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह घटनाएं मौजूदा बोर्ड के कार्यभार संभालने से पहले की हैं। उन्होंने बताया कि मामला पहले से अदालत में है और बोर्ड ने अपनी ओर से जवाब दाखिल कर दिया है। विजयन ने यह भी कहा कि 2022 से अब तक देवस्वोम से जुड़े छह हाथियों की मृत्यु हो चुकी है और उन सभी का पोस्टमॉर्टम वन विभाग की मौजूदगी में हुआ। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हाथी दांत की जब्ती का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए वर्तमान प्रबंधन पर दोष नहीं डाला जा सकता।

लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब पहले हुआ, तो इतने लंबे समय तक इसकी खबर दबाई क्यों गई? मंदिर जैसी संस्था, जहां हर वस्तु को भगवान की संपत्ति माना जाता है, वहां ऐसे भ्रष्टाचार का होना केवल वित्तीय अपराध नहीं बल्कि धार्मिक और नैतिक अपराध भी है। भक्त यह जानना चाहते हैं कि जिन आभूषणों, चांदी के दीपों और मुकुटों को वे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, वे आखिर किसके हाथों में गायब हो रहे हैं।

गुरुवायूर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। वहां का हर चांदी का दीप, हर मुकुट और हर बर्तन एक भक्त की आस्था की पहचान है। और जब आस्था के इन प्रतीकों में हेराफेरी होती है, तो यह केवल सोने-चांदी का नुकसान नहीं, बल्कि विश्वास का अपमान होता है। अब यह देखना होगा कि अदालत और सरकार इस पवित्र चोरी के पीछे की सच्चाई कब और कैसे उजागर करती है।

## नगालैंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल एनडीपीपी का एनपीएफ में विलय

**(जीएनएस)**। कोहिमा। नगालैंड की राजनीति में मंगलवार को ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला जब नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) का औपचारिक रूप से नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) में विलय कर दिया गया। कोहिमा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एनपीएफ के आम सम्मेलन में इस निर्णय को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इस अवसर पर करीब 5,000 सक्रिय सदस्य मौजूद रहे।

सम्मेलन में एनडीपीपी के विलय को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी गई। यह कदम पहले 18 अक्टूबर को हुई सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स (COB) और सेंट्रल एक्जीक्यूटिव काउंसिल (CEC) की बैठक में पारित प्रस्ताव की पुष्टि था। सम्मेलन के दौरान 2025-2030 की नई टीम का गठन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नेफियू रियो को एनपीएफ का नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि विधायक



अचुम्बेमो किकोन को महासचिव के पद पर बरकरार रखा गया।

नेफियू रियो के नेतृत्व में पार्टी ने राज्य में विकास और स्थायी शांति पर जोर देने का संकल्प लिया। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि रियो के मार्गदर्शन में पार्टी क्षेत्रीय राजनीति को और मजबूत करने, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा जनता के कल्याण के लिए नए कार्यक्रम लागू करेगी।

एनडीपीपी अध्यक्ष चिंगवांग कोन्याक के ऐतिहासिक निर्णय की भी विशेष सराहना की गई, जिन्होंने पार्टी को एनपीएफ में विलय कर राजनीतिक एकजुटता का संदेश दिया। पार्टी ने इसे नगालैंड की राजनीति में स्थायित्व और प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विलय से नगालैंड की राजनीति में नए सिरे से समीकरण बनेंगे। एनपीएफ अब राज्य में और अधिक संगठित और मजबूत होकर आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही, इस कदम से क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक विकास की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह की लहर है। सभी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि एनपीएफ और एनडीपीपी की एकजुटता राज्य की राजनीति में नई ताकत का परिचायक बनेगी और जनता के कल्याण के लिए प्रभावी नीतियां लागू करने में मदद करेगी।

## बेंगलुरु के गड्ढों को भरने को एक सप्ताह का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

**(जीएनएस)**। बेंगलुरु की सड़कें हमेशा से ही चालकों और पैदल यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण रही हैं, लेकिन हाल के महीनों में बारिश और मरम्मत में देरी के चलते गड्ढों की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। शहरवासियों की लगातार शिकायतों और विभिन्न कंपनियों की आलोचनाओं के बाद कर्नाटक सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि बेंगलुरु की सभी सड़कों के गड्ढे अगले एक सप्ताह के भीतर भरे जाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय सीमा के भीतर काम पूरा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सड़क सुधार कार्यक्रम के दौरान दिए। उन्होंने माना कि लगातार हुई बारिश के कारण कई मरम्मत कार्यों में देरी हुई, लेकिन अब यह स्थिति और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि गड्ढों की मरम्मत केवल अस्थायी समाधान नहीं है, बल्कि शहर की समग्र सड़क गुणवत्ता और यातायात की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।



सिद्धरमैया ने 'व्हाइट टॉपिंग' सड़क निर्माण तकनीक को स्थायी समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शहर के कई हिस्सों में मजबूत कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो 25 से 30 साल तक टिकाऊ रहती हैं और जिनमें बार-बार गड्ढे नहीं बनते। इसके अलावा, सरकार ने बेंगलुरु और विधानसभा क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। इस निवेश का उद्देश्य केवल सड़क मरम्मत नहीं बल्कि पूरे शहर की यातायात प्रणाली और विकास को मजबूत बनाना है।

इस बीच, फार्मास्युटिकल कंपनी बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार-शॉ ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की। शॉ ने सरकार को बेंगलुरु के विकास में सहयोग का आश्वासन दिया। किरण शॉ ने लंबे समय से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से बेंगलुरु की खराब सड़क स्थिति और शहर में फैली गंदगी की आलोचना की थी, जिसके चलते यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बन गया था।

मुलाकात के बाद उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि उद्योग जगत अब सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा, "वे (किरण शॉ) सहमत हैं कि वे बेंगलुरु के विकास में सक्रिय सहयोग करेंगी और शहर की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुँचने देंगे।" यह संकेत है कि सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल के साथ शहर की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा।

सड़क सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले महीनों में बेंगलुरु की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने और शहर की छवि सुधारने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। अधिकारियों को दिए गए अल्टीमेटम और उद्योग जगत के सहयोग से उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी की सड़कें जल्द ही सुरक्षित, टिकाऊ और चालक अनुकूल बनेंगी। यह कदम शहरवासियों के लिए राहत की खबर है और उम्मीद जताता है कि अब बेंगलुरु की सड़कें लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रहेंगी।

## राष्ट्रपति भवन के पास इमारत में लगी आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने 20 मिनट में पाया काबू

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली की दोपहर उस समय अचानक अफरातफरी में बदल गई जब राष्ट्रपति भवन के नजदीक स्थित एक इमारत में धुआं उठता देखा गया। यह घटना मंगलवार दोपहर लगभग 1:50 बजे की है, जब राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 31 के पास मौजूद नर्मदा अपार्टमेंट की दो मंजिला इमारत में आग लग गई। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों ने मात्र 20 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर पर आग की लपटें उठने लगीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत वहां मौजूद लोगों को बाहर निकालने में मदद की। दिल्ली पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर ट्रैफिक डायवर्ट किया, ताकि बचाव दल को सुचारू रूप से काम करने में कोई बाधा न हो।

फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि आग नर्मदा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 19 में लगी थी। आग लगने के सटीक कारणों का अभी



पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। घटनास्थल से जले हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वायरिंग के अवशेष बरामद हुए हैं।

दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग के फैलने से पहले ही उसे नियंत्रित कर लिया गया, जिससे ऊपर की मंजिलों तक लपटें नहीं पहुंचीं। अगर थोड़ी और देर हो जाती, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी क्योंकि इमारत राष्ट्रपति भवन परिसर के बेहद नजदीक है और सुरक्षा दृष्टि से यह इलाका संवेदनशील माना जाता है।

फायर डिपार्टमेंट की टीम और दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है। जांच दल यह पता लगाने की कोशिश में है कि आग शॉर्ट सर्किट, गैस लीक या किसी अन्य मानवीय लापरवाही के कारण लगी। स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि आग लगने के समय फ्लैट में कौन मौजूद था। इस हादसे ने राजधानी में फिर एक बार इमारतों में सुरक्षा मानकों और फायर अलार्म सिस्टम की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी के कई आवासीय परिसरों में अग्नि सुरक्षा उपकरण या तो काम नहीं करते या रखरखाव के अभाव में निष्क्रिय पड़े हैं। सौभाग्य से इस बार कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह घटना एक चेतावनी है कि सुरक्षा के मामलों में लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है।

### सूचना

**22, 23 व 24 अक्टूबर को नवर्षाभिनंदन, भय्यादूज व तीज पर्व के उपलक्ष्य में हमारा कार्यालय अवकाश मनायेगा। अतः 23, 24 व 25 अक्टूबर को समाचार पत्र नहीं प्राप्त हो सकेगा, आगामी अंक 26 अक्टूबर, 2025 रविवार से यथावत अंक प्रकाशित होंगे।**

**-सम्पादक**

## ऑपरेशन सिंदूर से अन्याय का बदला लेकर भारत ने दिखाया मर्यादा और शक्ति का संगम प्रधानमंत्री मोदी का दीपावली संदेश

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। दीपों के इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक भावनात्मक पत्र लिखकर शुभकामनाएं दीं और साथ ही भारत की नई सामरिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा को लेकर अपनी दृष्टि साझा की। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह दीपावली केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नए भारत के आत्मविश्वास, संयम और संकल्प का उत्सव है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले संपन्न हुआ "ऑपरेशन सिंदूर" भारत की उसी मर्यादित शक्ति का परिचायक है, जिसने अन्याय का उत्तर न्याय के साथ दिया, और शत्रु को यह संदेश दिया कि भारत शांतिप्रिय है, पर दुर्बल नहीं।

प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की न्यायप्रियता, नीति और नैतिक शक्ति का जीवंत उदाहरण है। यह कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक कर्म था। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान श्रीराम ने लंका विजय से पहले धर्म का पालन करते हुए भी असुरता का अंत किया, वैसे ही भारत ने भी संयम बनाए रखते हुए उस अत्याचार का उत्तर दिया जिसने देश की सीमाओं को चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल शत्रु को उसके स्थान पर उत्तर दिया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि भारत अपने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए अटल है। यह अभियान दिखाता है कि भारत की ताकत केवल उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, नीति और नीयत में भी निहित है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज भारत के अनेक ऐसे इलाके, जो वर्षों तक नक्सलवाद और माओवादी हिंसा से त्रस्त रहे, अब प्रकाशमय हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से कई नक्सल प्रभावित जिलों ने विकास की मुख्यधारा को अपनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज जिन इलाकों में कभी डर और हिंसा का अंधकार था, वहां अब दीपक की लौ है, स्कूलों की घंटियां हैं, बच्चों की हंसी है और किसानों की मुस्कान है। यह दीपावली उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने हिंसा को त्यागकर संविधान, विकास और शांति का मार्ग चुना है। यह वही आत्मबल है जो भारत को अजेय बनाता है।"

अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुए सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती के निर्णय ने आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाया है। "जीएसटी बचत उत्सव" के तहत जनता ने हजारों करोड़ रुपये की बचत की, जो कि भारत की आर्थिक नीतियों की पारदर्शिता और जनहित की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि "भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि विश्वास और व्यवस्था की विजय है।"प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, खान-पान में तेल का उपयोग दस प्रतिशत घटाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने लिखा, "हर व्यक्ति अगर एक छोटा परिवर्तन भी अपने जीवन में लाए, तो उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा। यह परिवर्तन का युग है — आत्मनिर्भर भारत का युग।"

## संपादकीय

# युद्ध का कारोबार और नोबेल

विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार, तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह वैश्विक शांति के लिए दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार की चाहत रखते रहे। नोबेल शांति पुरस्कार शांति, सहयोग और मानवता की उन्नति के लिए दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या युद्ध को बढ़ावा देकर या युद्धविराम का दावा करने वाली शक्तियों को यह पुरस्कार देना उचित होता है? अमेरिका का सामरिक हथियार व्यापार पांच से छह ट्रिलियन डॉलर का है।

पब्लिक डोमेन के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका छह से आठ प्रत्यक्ष युद्धों और तीस से चालीस प्रॉक्सी युद्धों में शामिल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग अपने जीने के अधिकार से वंचित हुए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले इसका ऐतिहासिक उदाहरण हैं। विश्व के हथियार व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग चालीस प्रतिशत है। एक अच्छा राष्ट्र वह है जो अपनी और गरीब राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए सामरिक सहायता दे, लेकिन अमेरिका हथियारों को व्यावसायिक रूप से उत्पादित करता है और 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत गरीब व विकासशील देशों के किसानों के हितों को नजरअंदाज करता है।

ट्रंप का दावा है कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराया। भारत ने इन दावों को खारिज किया है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने दो सौ बिलियन डॉलर के हथियार निर्यात किए, जिनमें सऊदी अरब और भारत के साथ सौदे शामिल थे। असल में अमेरिका भारत में अपनी कृषि सप्लाई चेन स्थापित करना चाहता है। देखा जाए तो अमेरिका का इतिहास शांति के बजाय हथियार व्यापार और भू-राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने का रहा है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक, अमेरिका ने युद्धों को बढ़ावा देने और हथियारों के व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाई है। ट्रंप की नीतियां, जैसे भारत पर टैरिफ और रूस-यूक्रेन युद्ध में हथियारों की आपूर्ति, उनकी 'शांति' की छवि पर सवाल उठाती हैं। नोबेल शांति पुरस्कार ऐसी शख्सियतों को दिया जाना चाहिए जो वास्तव में मानवता और शांति के लिए समर्पित हों। यह पुरस्कार उन शक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए जो युद्धों को बढ़ावा देकर युद्धविराम का श्रेय लेने का प्रयास करें। नोबेल शांति पुरस्कार समिति अमेरिकी राष्ट्रपतियों को डिफ़ॉल्ट रूप से इस पुरस्कार की पात्रता से बाहर रखे, क्योंकि उनकी नीतियां शांति के बजाय व्यापारिक और सामरिक हितों को प्राथमिकता देती हैं।

# बिहार में मतदान से पहले उलझ रहे राजनीतिक समीकरण... कैसे बढ़ी रहीं अलायंस में मुश्किलें

बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर मुश्किलें बनी हुई हैं। महागठबंधन में नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन अंतर्विरोधों ने चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है।

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही राजनीतिक समीकरण उलझते जा रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ NDA ने सीटों के बंटवारे की घोषणा तो कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर फंसा हुआ है। इस उलझन ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है।

चुनाव से काफी पहले से ही बिहार में दो मुख्य राजनीतिक खेमे साफ थे। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें करीब आईं, मामला पेचीदा होता चला गया। महागठबंधन के नेता, जो चुनाव से पहले एक साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, अब सीटों के बंटवारे पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ, NDA ने सीटों के बंटवारे की घोषणा में बाजी मार ली, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर ऐसा फंस गया कि गठबंधन की जमीनी हकीकत पर ही सवाल उठने लगे हैं। महागठबंधन में नेताओं के बीच चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले तो काफी मेलजोल दिखता था। लेकिन सीट बंटवारे की बातचीत शुरू होते ही उनके लिए एक नतीजे पर पहुंचना मुश्किल हो गया। बार-बार सीट बंटवारे की घोषणा का समय आगे खिसकाया गया। पहले नामांकन की आखिरी तारीख बीत गई, फिर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख भी निकल गई, और सहमति बनने की उम्मीद अधूरी रह गई। कम से कम पहले चरण के चुनाव के लिए तो यही कहानी रही। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल दोनों ही खेमों को परेशान कर रहा है। महागठबंधन में RJD की जिद के बावजूद कांग्रेस अभी तक CM फेस घोषित करने पर राजी नहीं हुई है। इस गठबंधन में CPI (ML) भी एक अहम सहयोगी है। उसने भी आधिकारिक तौर पर RJD नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से मना कर दिया है, लेकिन वह उनके नाम का समर्थन जरूर कर रही है। दूसरी तरफ NDA में, पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने और फिर LJP नेता चिराग पासवान ने यह बात दोहराई कि चुनाव के नतीजे आने के बाद विधायक मुख्यमंत्री तय करेंगे। इसके बाद JDU प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे।

**अंतर्विरोध का असरः** फिलहाल महागठबंधन में अंतर्विरोध सिर्फ कुछ सीटों तक सीमित दिख सकते हैं, जहां 'फ्रेंडली फाइट' यानी आपसी सहमति से चुनाव लड़ने की बात हो सकती है। वहीं NDA में, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए LJP और JDU लगभग हर सीट पर एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने दिख सकते हैं। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि BJP और JDU, अपना मुख्यमंत्री बनवाने की चाहत में, एक-दूसरे की सीटें किस हद तक बढ़ने देना चाहेंगे।

**दिलचस्प मुकाबला :** निश्चित रूप से, इन अंतर्विरोधों ने पहले से ही दिलचस्प इस चुनावी लड़ाई के सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। यह देखना बाकी है कि ये उलझनें चुनाव के नतीजों को कैसे प्रभावित करती हैं।

## प्रेरणा

### जब दुनिया अंधकार में थी, तब भारत जागा — ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित सभ्यता की अनंत कथा

जब पृथ्वी पर सभ्यता का शैशवकाल था, जब मानव अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने में असमर्थ था, जब विश्व के अधिकांश भाग अंधकार, भय और अज्ञानता में डूबे हुए थे — उसी काल में भारत की पवित्र भूमि पर कोई ऋषि हिमालय की गोद में ध्यानमग्न था, कोई मुनि नदी के तट पर वेदों की ऋचाएँ गा रहा था, और कोई ब्रह्मचारी अग्नि के सम्मुख बैठकर आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों का मनन कर रहा था। यह वह युग था जब पृथ्वी पर ज्ञान का एकमात्र सूर्य भारत से उदित हुआ। यहाँ ज्ञान मात्र शब्द नहीं, साधना था; यहाँ बुद्धि नहीं, अंतःकरण बोलता था। यहाँ 'जानना' का अर्थ था — स्वयं को पहचानना।

वेदों की ध्वनि जब ब्रह्मांड में गूंजी, तब मानव ने पहली बार यह अनुभव किया कि ज्ञान किसी पुस्तक का विषय नहीं, आत्मा की अनुभूति है। ऋषियों ने कहा — आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः — अर्थात् आत्मा को देखना, सुनना, सोचना और उसमें लीन होना ही सच्चा ज्ञान है। यही वह क्षण था जब भारत ने यह घोषणा की कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह ब्रह्म का अंश है। वेदों की ऋचाएँ सृष्टि की धड़कन के साथ जुड़ीं, और भारत ने पहली बार यह सिद्ध किया कि ध्वनि ही सृष्टि का प्रथम तत्व है।

हजारों वर्ष बीत गए, पर भारत की यह ज्ञान परंपरा रुकी नहीं। जब यूनान और रोम का अस्तित्व भी अस्पष्ट था, तब पाणिनि नामक ऋषि ने 'अष्टाध्यायी' नाम का ग्रंथ लिखा — एक ऐसा ग्रंथ जो केवल भाषा का नहीं, तर्क, गणित और कंप्यूटेशन का अनोखा संगम है। पाणिनि का हर सूत्र एक एल्गोरिथ्म की तरह कार्य करता है, जो आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की जड़ों में निहित है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हजारों वर्ष पहले एक भारतीय व्याकरणाचार्य ने वह संरचना दी, जिससे आधुनिक कंप्यूटर भाषा विकसित हो सकती थी। यही कारण है कि आज विश्व के बड़े विश्वविद्यालय 'पाणिनियन व्याकरण' को कंप्यूटर विज्ञान के प्रारूप के रूप में पढ़ाते हैं।

भारत की ध्वनि परंपरा भी अद्वितीय थी। प्रातिशाख्य ग्रंथों में बताया गया कि किस ध्वनि के उच्चारण के लिए जीभ कहाँ ठहरे, श्वास किस गति से निकले, और स्वर किस बिंदु से उत्पन्न हो। यह केवल भाषाशास्त्र नहीं, कंपन-विज्ञान (vibration science) का सबसे पुराना सिद्धांत था। भारत ने यह समझ लिया था कि ध्वनि केवल वाणी नहीं, ऊर्जा है। यही कारण है कि मंत्रों के जप से आज भी मानव मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती हैं — यह भारतीय ध्वनि-विज्ञान की कालातीत उपलब्धि है। पतंजलि ने जब योग सूत्र रचा, तो उन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे हुए चेतना के विज्ञान को उजागर किया। "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" — इस एक वाक्य में समस्त मनोविज्ञान, तंत्रिका-विज्ञान और अध्यात्म का सार छिपा है। योग केवल आसन नहीं, यह मन की समस्त तरंगों को शांत करने का विज्ञान है। यह वह साधना है जिससे मनुष्य अपने मन के पार जाकर 'स्व' का अनुभव करता है। आज न्यूरोसाइंस और मनोचिकित्सा जिस 'माइंडफुलनेस' की बात करते हैं, वह पतंजलि के योग का ही आधुनिक रूप है। भारत ने मन और शरीर दोनों का संतुलन बनाया — इसलिए यहाँ ज्ञान हमेशा मानवता से जुड़ा रहा, न कि केवल प्रयोग से।

जब पश्चिम यह मानता था कि पृथ्वी समतल है, तब आर्यभट ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा का सिद्धांत दिया, जो कोपरनिकस से हजारों वर्ष पहले कहा गया। भास्कराचार्य ने 'लीलावती' और 'बीजगणित' के माध्यम से गणित को भावनात्मक और तर्कपूर्ण दोनों बनाया। उन्होंने समय, गति, और ग्रहों की स्थिति का गणनात्मक सूत्र प्रस्तुत किया। उनके सूत्रों ने आधुनिक गणित और खगोलशास्त्र की नींव रखी।

चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने जो कार्य किया, वह भी अनुपम था। चरक ने मानव शरीर को केवल भौतिक यंत्र नहीं, बल्कि पंचमहाभूतों का संतुलन कहा। सुश्रुत ने शल्यचिकित्सा की तकनीकें विकसित कीं, और वाग्भट ने शरीर और मन के समरस संबंध पर बल दिया। भारत का चिकित्सा-विज्ञान 'आरोग्य' को केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा, मन और प्रकृति के संतुलन की अवस्था मानता था। यही कारण है कि आयुर्वेद में आहार, व्यवहार, भाव और विचार — चारों को समान रूप से महत्व दिया गया।

भारतीय मनीषियों ने कभी भी विज्ञान और अध्यात्म को अलग नहीं किया। भगवद्गीता में कृष्ण कहते हैं — ज्ञानं विज्ञानसहितम् — अर्थात् सच्चा ज्ञान वही है जो विज्ञान के साथ जुड़ा हो। यहाँ ज्ञान प्रयोगशाला का विषय नहीं, जीवन का विषय है। इसलिए भारत में शोध केवल प्रयोग नहीं, तपस्या थी।

सांख्य के महर्षि कपिल ने सृष्टि के द्वैत तत्वों — पुरुष और प्रकृति — का गहन विश्लेषण किया। कणाद ने परमाणु की अवधारणा दी, जब आधुनिक विज्ञान के पास सूक्ष्म पदार्थ की कोई परिभाषा ही नहीं थी। गौतम ने न्याय दर्शन के माध्यम से प्रमाण और तर्क की प्रणाली दी। बादरायण ने वेदांत में ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का रहस्य खोला। और जब शंकराचार्य ने कहा — "ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या," तो उन्होंने केवल दार्शनिक विचार नहीं दिया, बल्कि यह बताया कि चेतना ही अंतिम सत्य है।

भारत की इस ज्ञान धारा का सर्वोच्च प्रतीक है 'शून्य'। जब आर्यभट ने शून्य की अवधारणा दी, तब उन्होंने कहा कि यह केवल 'कुछ नहीं' नहीं, बल्कि 'सब कुछ' की संभावना है। शून्य वह स्थान है जहाँ सृष्टि प्रारंभ होती है और वहीं समाप्त होती है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने शून्यता को अस्तित्व और अनस्तित्व के मध्य की स्थिति कहा — यही सृष्टि का रहस्य है। आज की क्वांटम फिजिक्स जब 'वैक्यूम एनर्जी' और 'क्वांटम फील्ड' की बात करती है, तो वह उसी शून्य के दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या है, जो भारत ने हजारों वर्ष पहले किया था।

भारत ने ज्ञान को मनुष्य की आत्मा से जोड़ा, इसलिए उसका विज्ञान नैतिक रहा, उसका दर्शन मानवीय रहा, और उसकी संस्कृति करुणामयी रही। जब दुनिया में युद्ध और विस्तार का विज्ञान पनपा, भारत में आत्मा और एकता का विज्ञान विकसित हुआ। यही कारण है कि भारत की सभ्यता आज भी जीवित है — क्योंकि यह सभ्यता मिट्टी से नहीं, आत्मा से बनी है। आज जब पश्चिमी विश्वविद्यालय योग, आयुर्वेद और वेदांत पर शोध कर रहे हैं, तो यह भारत के पुनर्जागरण का संकेत है। यह प्रमाण है कि भारत की प्रज्ञा कालातीत है। दुनिया की हर नई खोज, हर नई तकनीक, हर नई वैज्ञानिक अवधारणा कहीं न कहीं उसी वैदिक दृष्टि का विस्तार है — जो कहती थी कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। भारत ने यह सिखाया कि ब्रह्मांड का रहस्य किसी दूर ग्रह या यंत्र में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में छिपा है। जब तक यह सत्य जीवित रहेगा, तब तक भारत की वेदना, उसकी वाणी और उसका ज्ञान अमर रहेगा — क्योंकि यही वह भूमि है जिसने अंधकार में प्रकाश, अज्ञान में अनुभूति और मृत्यु में भी अमरत्व की खोज की।

# ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा असर कि होश खो बैठा पाकिस्तानी जनरल, बातें सुन माथा पीट लेंगे आप

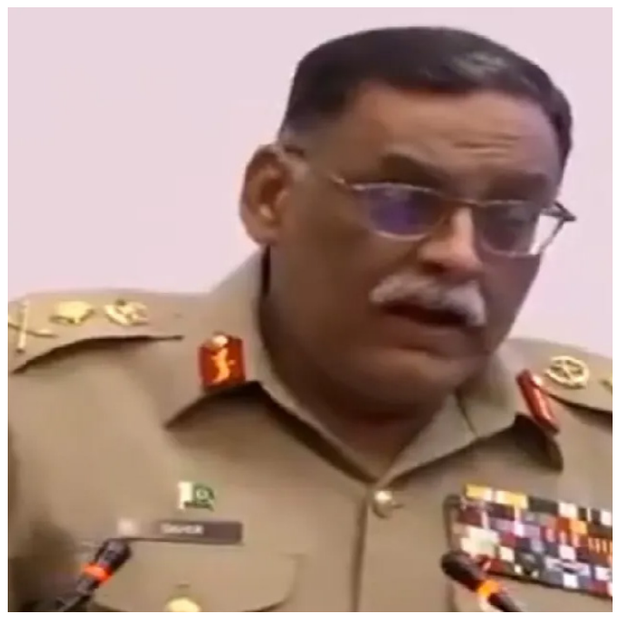

भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ-साथ आर्मी के बड़े जनरलों की नींद उड़ा दी है। भारत की मार का असर ऐसा हुए है कि, चोट दिमाग में लगी है और जिसके मन जो आ रहा है वही बक दे रहा है। अब ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने कहा है जिसकी बातें सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। जनाब की बाते सुनकर आपको हंसी तो आएगी ही, तरस भी आएगा। पाकिस्तान में सेना के एक बड़े अधिकारी हैं। इन जनाब का नाम जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है। मिर्जा साहब इतने बौखलाए हुए हैं कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। जनरल मिर्जा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मिर्जा कहते हुए नजर आ रहे हैं, 'भारत की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है।' आप समझ सकते हैं कि जो सेना खुद पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, जिस पाकिस्तान में सैन्य शासन का लंबा इतिहास रहा हो उसके सैन्य अधिकारी का दिमाग क्या सोचता होगा। इतना ही नहीं जनाब ने और भी बहुत कुछ कहा है चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल, पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला तो कुछ भी बोल गए। मिर्जा साहब ने कहा, "भारतीय सेना राजनीतिक हो चुकी है।" उन्होंने कहा कि अगली जंग कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगी। वैसे जनाब भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर भी कश्मीर तक सीमित नहीं था। जनरल मिर्जा ने आगे कहा, "हमने 96 घंटे अपने संसाधनों पर लड़ाई लड़ी और भारत प्रभुत्व के लिए सैन्य शक्ति और पश्चिमी समर्थन का इस्तेमाल करता है।" जनरल मिर्जा की आर्मी ने कैसी लड़ाई लड़ी पूरी दुनिया ने इसकी तस्वीरें देखी हैं।

शमशाद मिर्जा इतने पर ही नहीं रुके, जमकर बोले और अपने देश की पोल खोलते गए। मिर्जा ने कहा, "कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन किया जाना चाहिए।" अब यहां यह समझना चाहिए कि PoK से पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव यही बात तो कहता है। खैर ये समझ की बात है जिसकी पाकिस्तानियों से उम्मीद बेमानी है। इसके बाद को जनरल वो बोल गए जिसके बारे में सुन-सुनकर दुनिया के कान पक गए हैं, वही परमाणु बम की फुस्की धमकी। मिर्जा ने कहा, ''दक्षिण एशिया में परमाणु टकराव का खतरा है।'' पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एक नई बात जरूर रही है। मिर्जा ने कहा, ''भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है।'' मिर्जा के इस बयान से साफ है कि पानी रुकने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल है। गर्मी और तड़क-भड़क दिखाने के बाद मिर्जा ने शांति के कबूतर उड़ाए और सुरक्षा की गुहार भी लगाने लगे। जनरल साहब ने कहा ''हम समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा चाहते हैं।''

## अभियान

# गोवर्धन पूजा और 56 भोग का दिव्य रहस्य

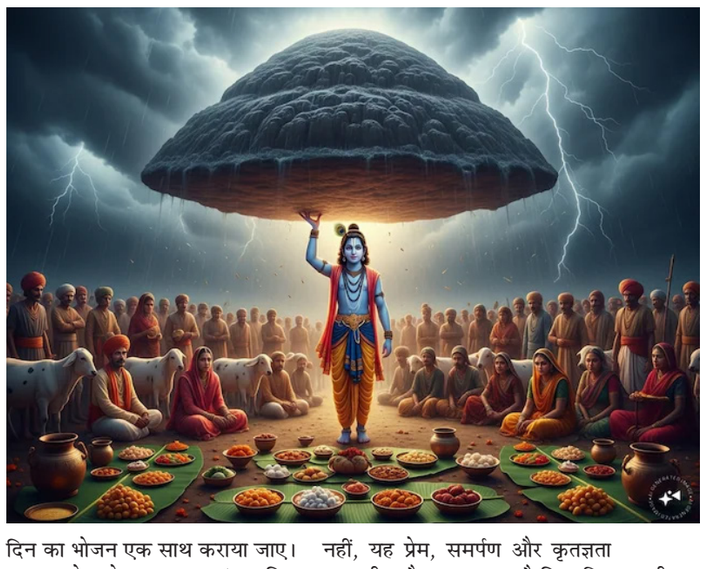

दीपावली के दूसरे दिन आने वाला गोवर्धन पूजा पर्व केवल पूजा-पाठ का नहीं, बल्कि भक्ति, कृतज्ञता और प्रेम का उत्सव है। यह वही दिन है जब श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। उस क्षण से यह पर्व भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक बन गया। कथा के अनुसार जब श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को बताया कि इंद्र के स्थान पर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें अन्न, जल, वृक्ष और जीवन देता है, तब इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा कर दी। ब्रजवासियों ने श्रीकृष्ण की शरण ली, और बालगोपाल ने सहज भाव से गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठा पर उठा लिया। सात दिनों तक उन्होंने पर्वत को थामे रखा, ताकि ब्रजवासियों और गौमाता को वर्षा से बचाया जा सके।

सात दिन तक श्रीकृष्ण ने अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब इंद्र का अहंकार टूटा और वर्षा थमी, तब ब्रजवासियों ने हर्षपूर्वक गोवर्धन पूजा की। माता यशोदा और ब्रज की गोपियों ने सोचा कि कान्हा ने सात दिनों तक कुछ नहीं खाया, इसलिए उन्हें सात दिन का भोजन एक साथ कराया जाए। माता यशोदा रोज आठ पहर (एक दिन में आठ भोजन) कराती थीं — सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि आदि में अलग-अलग व्यंजन। इस तरह 7 दिन × 8 पहर = 56 भोग तैयार किए गए। यही "छप्पन भोग" की परंपरा का आरंभ माना गया।

छप्पन भोग केवल व्यंजनों का समूह नहीं, यह प्रेम, समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह बताता है कि भक्ति में कोई सीमा नहीं होती। जब भक्त अपने प्रभु से प्रेम करता है, तो वह उसे अन्न नहीं, भावना का स्वाद खिलाता है।

अब जानते हैं कि छप्पन भोग में क्या-क्या शामिल होता है। यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र में व्यंजनों की सूची कुछ अलग हो सकती है, परंतु पारंपरिक रूप से छप्पन भोग में मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे और कसैले — हर स्वाद का समावेश होता है। इसमें प्रमुख रूप से ये व्यंजन रखे जाते हैं:

1. माखन-मिश्री – श्रीकृष्ण का प्रियतम भोग, उनके बाल्यकाल का स्मरण।
2. मालपुआ, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, खीर, रबड़ी, गुजिया, जलेबी, हलवा, बालूशाही, मोहनथाल, श्रीखंड, खाजा जैसे मीठे पकवान।
3. पूरी, कचौरी, परांठा, दाल-बाटी, मठरी, सेव, चिवड़ा, भुजिया, दही-बड़ा, पकोड़ी जैसे नमकीन और तृप्तिदायक व्यंजन।
4. सब्ज़ियाँ – लौकी की सब्ज़ी, आलू-टमाटर की रसदार भुजिया, कद्दू की सब्ज़ी, तोरी, बैंगन, भिंडी, परवल और चोख्यानी सब्ज़ियाँ।
5. दलहन – मूंग-दाल, उड़द-दाल, चना-दाल, तूर-दाल आदि।
6. अनाज और पकवान – चावल, जीरा-राइस, खिचड़ी, पुलाव, साबूदाना खिचड़ी, मीठा चावल।
7. फल – केले, सेब, अंगूर, अनार, नारियल, अमरूद, संतरा, और मौसमी फल।
8. पान, मिश्री, इलायची, लौंग, सूखे मेवे, और पंचामृत – जिन्हें अंत में प्रसाद के रूप में रखा जाता है।
9. माखन और दूध से बने पकवान – मक्खन मलाई, दूध पाक, खोया बर्फी, दूध पेड़ा।

इन व्यंजनों को पीतल या मिट्टी के पात्रों में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। इसके बीच में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक स्वरूप — गाय के गोबर से निर्मित आकृति — रखी जाती है, जिसे फूलों, पत्तियों, तुलसी-दल और दीपों से सजाया जाता है। फिर ब्रजवासी या श्रद्धालु "गोवर्धन महाराज की जय" कहते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं और छप्पन भोग अर्पित करते हैं।

छप्पन भोग के पीछे छिपा दर्शन यह है कि जब भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो संख्या भी प्रतीक बन जाती है। 56 का अर्थ केवल गणना नहीं, सात दिनों की साधना और आठ पहरों की सेवा का योग है। यह याद दिलाता है कि भक्ति का मूल तत्व 'समर्पण' है — जब भक्त अपने समय, श्रम और प्रेम का हर अंश अर्पित कर देता है, तब वही सच्चा भोग बनता है। आज भी मथुरा, वृंदावन, नाथद्वारा, द्वारका और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को छप्पन भोग लगाया जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथजी का छप्पन भोग विशेष प्रसिद्ध है, जहाँ घंटों तक भक्तजन भगवान के सम्मुख खड़े रहते हैं और वह क्षण अनुभव करते हैं जब भक्ति का स्वाद, अन्न के स्वाद से ऊपर उठ जाता है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा का अर्थ है — अपने अहंकार का त्याग और अपनी क्षमता का पूर्ण समर्पण। 56 भोग उस अर्पण का प्रतीक है जिसमें केवल व्यंजन नहीं, भावनाएँ परोसी जाती हैं। यह पर्व याद दिलाता है कि भगवान को अन्न नहीं चाहिए, उन्हें हमारा प्रेम चाहिए — वही प्रेम जो माता यशोदा ने अपने बालक को सात दिनों के उपवास के बाद छप्पन भोग के रूप में खिलाया था।जब दीपक की लौ के सामने छप्पन भोग सजे होते हैं, तो ऐसा लगता है मानो सारा ब्रह्मांड कह रहा हो — "जहाँ प्रेम है, वहीं परमात्मा है।"

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

# दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश: सद्गुरु से जुड़े फर्जी एआई विज्ञापनों पर गूगल को रोक लगाने के निर्देश, डीपफेक पर कार्रवाई के लिए कहा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। डिजिटल युग में बढ़ते फर्जी एआई कंटेंट और डीपफेक विज्ञापनों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने गूगल को निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म, विशेषकर यूट्यूब पर सद्गुरु की एआई-निर्मित झूठी तस्वीरों और गिरफ्तारी जैसे भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाए। अदालत ने कहा कि तकनीकी क्षमता रखने के बावजूद अगर कोई प्लेटफॉर्म इस तरह की गलत सूचनाओं को फैलने देता है, तो यह जनता को गुमराह करने और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के समान है।



यह आदेश 14 अक्टूबर को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने सुनाया। उन्होंने कहा कि "डीपफेक और झूठे एआई विज्ञापन समाज में भ्रम फैलाने और वास्तविकता को विकृत करने का माध्यम बनते जा रहे हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बनाए रखें और समय पर हस्तक्षेप करें।"
अदालत ने स्पष्ट किया कि डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति की छवि को विकृत करना या झूठे आरोपों से जोड़ना संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त 'व्यक्तिगत गरिमा' के अधिकार का उल्लंघन है।
सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उनके नाम और चेहरे का गलत उपयोग करके भ्रामक विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। इन विज्ञापनों में सद्गुरु की झूठी गिरफ्तारी, राजनीतिक बयानों और तथाकथित "विवादित निवेश योजनाओं" जैसी फर्जी सूचनाएं प्रसारित की जा रही थीं। फाउंडेशन ने बताया कि वे कई बार इन विज्ञापनों की शिकायत गूगल को कर चुके हैं, लेकिन हर बार नए नामों और नए लिंक से ऐसे फेक वीडियो फिर उभर आते हैं। अदालत में फाउंडेशन की ओर से यह भी कहा गया कि एआई तकनीक का दुरुपयोग अब इस स्तर पर पहुंच चुका है कि आम व्यक्ति के लिए असली और नकली में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गूगल को आदेश दिया कि वह तुरंत इस प्रकार के सभी वीडियो और विज्ञापनों की पहचान कर उन्हें प्लेटफॉर्म से हटाए। जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि यदि गूगल किसी तकनीकी या नीतिगत कारणवश ऐसे वीडियो हटाने में असमर्थ है, तो उसे हलफनामे के माध्यम से अदालत को यह बताना होगा कि किस स्तर पर बाधा उत्पन्न हो रही है और भविष्य में इससे बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
अदालत ने कहा, "टेक्नोलॉजी जितनी शक्तिशाली होती है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। डीपफेक्स न केवल व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि समाज में असत्य को स्थापित करने का माध्यम बनते जा रहे हैं।"
अदालत ने गूगल और ईशा फाउंडेशन को एक साथ बैठकर इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने का निर्देश भी दिया। अदालत ने सुझाव दिया कि एक ऐसा "रियल-टाइम कंटेंट प्रिवेंशन मैकेनिज्म" तैयार किया जाए, जिससे फाउंडेशन या किसी अन्य संस्था को बार-बार शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रणाली के अंतर्गत जैसे ही किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग होता हुआ पाया जाए, वैसी सामग्री स्वतः ब्लॉक हो जाए।
जस्टिस अरोड़ा ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को केवल "होस्टिंग सर्विस" के रूप में नहीं, बल्कि एक "डिजिटल प्रहरी" के रूप में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि "एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें मानवता की सेवा के लिए बनी हैं, न कि भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने के लिए। जो कंपनियां इन तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका प्रयोग नैतिक सीमाओं में रहे।"
अदालत का यह आदेश ऐसे समय आया है जब डीपफेक और एआई-जनित फर्जी वीडियो दुनियाभर में चिंता का विषय बन चुके हैं। हाल के महीनों में कई प्रसिद्ध हस्तियों, राजनीतिज्ञों और आध्यात्मिक गुरुओं के नकली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दिशा में न्यायपालिका का यह निर्णय डिजिटल नैतिकता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
देश में एआई और डीपफेक से जुड़े कानूनी ढांचे पर भी अब गंभीर विमर्श शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह रुख न केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी नीतियों और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बाध्य करेगा।
इस मामले में अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में होगी, जहां गूगल को अपनी प्रगति रिपोर्ट और प्रस्तावित तकनीकी समाधान अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो गूगल पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
डिजिटल दुनिया के इस दौर में जहां सच और झूठ की रेखा धुंधली होती जा रही है, दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश न केवल एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा का प्रयास है, बल्कि पूरे डिजिटल समाज को एक चेतावनी भी — कि तकनीक का प्रयोग सत्य और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए, न कि प्रचार और भ्रम के लिए।

# जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर केंद्र का बड़ा कदम, राज्यों से मांगी गई ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रहे उन ठेकेदारों, निरीक्षण एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों का पूरा ब्यौरा तुरंत भेजें, जिन पर किसी भी प्रकार की वित्तीय या तकनीकी अनियमितता का आरोप लगा है। सरकार ने कहा है कि अब इस योजना में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, यह निर्देश जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा जारी किया गया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए हर कार्य की जवाबदेही तय की जाएगी। मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे उन सभी ठेकेदारों और "थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियों" की सूची साझा करें, जिन पर जुर्माना लगाया गया है या जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है।
केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि उन सरकारी अधिकारियों की जानकारी भी दी जाए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें घटिया निर्माण, धन के दुरुपयोग, फर्जी बिलिंग या कार्य में देरी जैसी शिकायतें शामिल हैं। विभाग ने कहा है कि अधिकारियों के निलंबन, बर्खास्तगी, या उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा भेजा जाए। प्रत्येक मामले का एक पृष्ठ का सारांश रिपोर्ट के साथ संलग्न करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मंत्रालय को एक समग्र तस्वीर मिल सके कि किस स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही हुई और राज्यों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।
सूत्र बताते हैं कि केंद्र ने यह सख्त कदम मिशन की हालिया उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उठाया है। उस बैठक में पाया गया कि कई राज्यों में परियोजनाओं में दोहरी प्रविष्टियाँ (डुप्लिकेट एंट्री) की जा रही हैं, कार्यों में देरी हो रही है, और कुछ जगहों पर निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद भुगतान जारी कर दिया गया। मंत्रालय ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब जमीनी सत्यापन (Ground Truthing) के ज़रिए डाटा की सटीकता जांची जाएगी। इस प्रक्रिया में मौके पर जाकर यह देखा जाएगा कि रिपोर्ट में दर्ज कार्य वास्तव में पूरे हुए हैं या नहीं।
जल जीवन मिशन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक है, का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। लेकिन कई राज्यों से भ्रष्टाचार और तकनीकी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। मंत्रालय ने माना कि मिशन की प्रगति असमान रही है — कुछ राज्यों ने तेजी से काम पूरा किया, जबकि कुछ राज्यों में फाइलों पर ही योजनाएं अटकी हुई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि मिशन की मूल समयसीमा 2024 तय की गई थी, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय देरी को देखते हुए अब इस योजना को 2028 तक बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि इस अवधि में योजना की पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित हों। इसके लिए सरकार अब एक केंद्रीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से प्रत्येक परियोजना की प्रगति, खर्च और गुणवत्ता की निगरानी सीधे मंत्रालय के स्तर पर की जाएगी।
केंद्र के ताजा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्यों को अपने सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और उसे मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा जिन परियोजनाओं में गंभीर अनियमितता पाई गई है, उनकी जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी नियुक्त की जाएगी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जल शक्ति मंत्रालय की मंशा यह सुनिश्चित करने की है कि "हर घर जल" का सपना भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी राज्य में ठेकेदारों या अधिकारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
केंद्र सरकार के इस आदेश से राज्यों के जल विभागों में हलचल मच गई है। कई राज्यों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है और ठेकेदारों की कार्य सूची और भुगतान विवरण की दोबारा जांच की जा रही है।
नीति विशेषज्ञों का कहना है कि जल जीवन मिशन की सफलता न केवल पेयजल की उपलब्धता से जुड़ी है, बल्कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता से भी गहराई से संबंध रखती है। यदि भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम लगाई गई, तो यह योजना आने वाले वर्षों में भारत के ग्रामीण जीवन को बदलने का आधार बन सकती है।
इस बीच, मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही एक राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, जिसमें राज्यों की प्रगति, खामियां और सुधार के सुझाव शामिल होंगे। इस रिपोर्ट को संसद की स्थायी समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।
केंद्र का यह कदम संकेत देता है कि सरकार अब "नीति की घोषणा" से आगे बढ़कर "नीति के क्रियान्वयन" की ईमानदार निगरानी के दौर में प्रवेश कर चुकी है — जहां हर बूँद पानी की तरह हर रुपये की गिनती भी होगी, और हर गलती का हिसाब भी।

# पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने किया बांद्रा टर्मिनस का दौरा

## त्योहारों की भीड़ के मद्देनज़र यात्री सुविधाओं का निरीक्षण,तथा भीड़ प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा की





(जीएनएस)। दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीज़न के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 21 अक्टूबर 2025 को बांद्रा टर्मिनस स्टेशन का दौरा किया तथा अत्यधिक यात्री यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यात्री सुविधाओं, भीड़ प्रबंधन व्यवस्था और स्पेशल ट्रेन परिचालन का विस्तृत निरीक्षण किया। उनके साथ पश्चिम रेलवे मुख्यालय और मुंबई सेंट्रल मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरे के दौरान महाप्रबंधक ने बांद्रा टर्मिनस के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कॉनकोर्स, होल्डिंग एरिया, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय और सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया तथा त्योहारों के दौरान आने वाली भीड़ को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए स्टेशन की तैयारियों की समीक्षा की।
निरीक्षण के बाद श्री विवेक कुमार गुप्ता ने मीडिया को संबोधित किया और उन्हें त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को प्रबंधित करने तथा यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा किए गए व्यापक प्रबंधों के बारे में जानकारी दी।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान महाप्रबंधक ने बताया कि भारतीय रेल द्वारा वर्तमान त्योहारी सीज़न के दौरान हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों के 12,000 से अधिक फेरे परिचालित किए जा रहे हैं। देश भर के प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि 12 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी इस अवधि के दौरान यात्रियों के लिए सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों पर आने वाली भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे लगभग 80 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के 2,400 से ज़्यादा फेरे चला रही है, जिनमें से ज़्यादातर उत्तर भारत की ओर जाती हैं। इनमें से 1,586 फेरे गुजरात से, 738 महाराष्ट्र से और 90 मध्य प्रदेश से हैं। इनमें अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के लगभग 50 फेरे भी शामिल हैं।
श्री गुप्ता ने कहा कि टिकटिंग में आसानी के लिए मोबाइल यूटीएस सुविधा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से बुकिंग कर्मचारी टिकट जारी करने के लिए सीधे यात्रियों से संपर्क करते हैं। यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को प्रबंधित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अतिरिक्त कर्मियों को स्टेशनों पर तैनात किया गया है, ताकि यात्रियों का मार्गदर्शन किया जा सके और कतारों में सुरक्षित, व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। नियमित और विशेष सेवाओं सहित ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरपीएफ कर्मियों द्वारा सुरक्षा की जा रही है।
श्री गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सीसीटीवी सिस्टम पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। सभी संवेदनशील स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए वॉर रूम स्थापित किए गए हैं, जहाँ पश्चिम रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी चौबीसों घंटे मौजूद रहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर निःशुल्क पेयजल और पर्याप्त शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
बांद्रा टर्मिनस पर त्योहारों के दौरान अत्यधिक भीड़ को संभालने के लिए विशेष उपाय लागू किए गए हैं। 15 से 21 अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान लगभग 70,000 यात्री बांद्रा टर्मिनस से अपने गंतव्य तक यात्रा कर पाए। इस अवधि के दौरान यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए उधना/सूरत से 466, बांद्रा टर्मिनस से 468, मुंबई सेंट्रल से 254 और वलसाड से 72 फेरे चलाए गए। श्री गुप्ता ने आगे बताया कि भीड़ के सुचारू आवाजाही और यात्री सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बांद्रा टर्मिनस पर 450 यात्रियों की क्षमता वाला 350 वर्ग मीटर का एक अस्थायी होल्डिंग एरिया एवं 1,000 यात्रियों की क्षमता वाला 702 वर्ग मीटर का एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। दोनों होल्डिंग एरिया में पर्याप्त रोशनी, पंखे और एक सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली है, ताकि यात्रियों को ट्रेनों की आवाजाही की जानकारी मिलती रहे। बांद्रा टर्मिनस पर यात्रियों की सहायता के लिए प्रतिदिन दो पालियों में कुल 70 लाइसेंस प्राप्त सहायक तैनात रहते हैं। सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर चौबीसों घंटे पर्याप्त संख्या में टिकट चेकिंग स्टाफ भी तैनात रहते हैं एवं यात्रियों की अत्यधिक संख्या को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं।
भीड़ नियंत्रित करने के लिए मुंबई सेंट्रल मंडल के बांद्रा टर्मिनस, वापी और सूरत स्टेशनों पर प्लेटफ़ॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर पार्सल का ढेर न लगाने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि त्योहारों के दौरान होने वाली भारी भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सभी मंडलों में निरंतर निगरानी और समन्वित प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने, मोबाइल टिकटिंग सुविधाओं का उपयोग करने और सुरक्षित एवं परेशानी मुक्त यात्रा के लिए रेलवे कर्मचारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।

# केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जमीनी स्तर पर व्यवस्था का आकलन किया

## यात्रियों ने भारतीय रेल की बेहतर उत्सव व्यवस्था की प्रशंसा की, अनारक्षित डिब्बों में भी आरामदायक यात्रा की सूचना

- 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्री सुरक्षित और समय पर घर पहुंचें: अश्विनी वैष्णव
- पिछले 20 दिनों में, 4211 विशेष ट्रेनों ने 1 करोड़ से अधिक यात्रियों की सेवा की, त्यौहारों की भीड़ को कम करने के लिए 7800 और ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा
- औसतन प्रतिदिन 4.25 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा रही है
- रेल भवन और सभी जोन और डिवीजनों में समर्पित वॉर रूम सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए तत्क्षण यात्री यात्रा की निगरानी कर रहे हैं
- भारतीय रेल त्यौहारों की भीड़ के दौरान लोगों की सेवा में मानवीय स्पर्श, समर्पित होल्डिंग क्षेत्रों के अलावा, एम-यूटीएस सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर, यात्रियों को पीने योग्य पानी की सुविधा और स्वच्छ वॉशरूम प्रदान किए गए

(जीएनएस)। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और इस त्योहारी सीजन के दौरान रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए, उन्होंने बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन विशेष ट्रेनों से अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा दी जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि औसतन लगभग 4.25 लाख यात्री प्रतिदिन दिल्ली क्षेत्र से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और यहां तक कि चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल और ज़ोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है।
केंद्रीय मंत्री ने प्लेटफार्म संख्या 1 से होते हुए आरपीएफ नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, जो पूरे स्टेशन पर नज़र रखता है। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की।
श्री वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 16 पर पटना जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस के यात्रियों से भी बातचीत की। यात्रियों ने भारतीय रेलवे द्वारा उनके लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया (यात्री सुविधा केंद्र) का भी दौरा किया।
निरीक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा करने से पहले रेल भवन वॉर रूम से विशेष ट्रेनों की जानकारी की भी समीक्षा की। यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
भारतीय रेल त्योहारी सीजन के दौरान 12,011 विशेष ट्रेनें चला रहा है, ताकि यात्रा मांग में तेज वृद्धि को पूरा किया जा सके, जो 2024 में 7,724 ट्रेनों से उल्लेखनीय वृद्धि है।
नियमित रेल सेवाओं के अलावा, भारतीय रेल ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 के बीच 4,211 विशेष रेलगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिनसे 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा मिली है। दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रेल आने वाले दिनों में लगभग 7800 और विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है।
1 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच, इन विशेष ट्रेनों द्वारा 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की जा चुकी है। नई दिल्ली क्षेत्र में, 16 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच 21.04 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 19.71 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई थी, इस प्रकार 1.33 लाख यात्रियों की वृद्धि हुई।
देश भर में यात्री सुविधाओं को मजबूती भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा और आराम को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है। सभी स्टेशनों पर यात्री प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया गया है, जिसमें सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए समर्पित होल्डिंग क्षेत्र, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।
भारतीय रेल ने त्योहारों के मौसम में आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ की निगरानी और प्रबंधन के लिए रेल भवन में एक समर्पित "वॉर रूम" स्थापित किया है। यह कमांड सेंटर तत्क्षण निगरानी रखने में सक्षम है और अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का त्वरित समाधान करने में सक्षम बनाता है। यह पहल केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उनके मार्गदर्शन में स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना है।
श्री वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सतीश कुमार, यात्रियों की आवाजाही की समीक्षा करने और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के लिए समय-समय पर रेल भवन वॉर रूम का दौरा करते हैं। आज, यह वॉर रूम पूरे भारतीय रेल नेटवर्क की निगरानी करने वाली एक प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर 80 से अधिक वॉर रूम सक्रिय हैं।
इसी प्रकार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री व्यवस्थाओं पर बारीकी से निगरानी रखने, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और यात्रियों के लिए अधिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक छोटा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
जयपुर स्टेशन पर यात्रियों को विशेष मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली (एम-यूटीएस) के माध्यम से सीधे होल्डिंग एरिया में टिकट जारी किए जा रहे हैं, जिससे स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल रही है और यात्रियों को सुविधाजनक और संतोषजनक अनुभव मिल रहा है। पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल भी यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 1 अक्टूबर से अब तक, वडोदरा मंडल द्वारा संचालित नियमित और 5 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 30 लाख से अधिक यात्री उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित अपने गंतव्यों तक पहुंच चुके हैं। मंडल द्वारा पांच त्यौहार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनके 70 से अधिक फेरे पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।
यात्री सुविधा के तहत, व्यस्त यात्रा समय के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच 5,000 पैकेज्ड पेयजल बोतलें वितरित की गईं।
तंजावुर जंक्शन पर एक हालिया उदाहरण, जहां बुजुर्ग यात्रियों ने स्वच्छ सुविधाओं के साथ वातानुकूलित विश्राम कक्षों का लाभ उठाया। उन्होंने विषम समय में भी आराम और सुविधा सुनिश्चित की। यात्रियों ने भी भारतीय रेलवे के अपने बेहतर यात्री अनुभव के हिस्से के रूप में विचारशील, सेवा-उन्मुख सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया।

**भ्रामक सूचना का मुकाबला करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना**

भारतीय रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चालू त्यौहारी सीजन के दौरान सतर्कता से काम कर रही है, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम भी उठा रही है।
यह संज्ञान में आया है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल यात्रियों में अनावश्यक दहशत पैदा करने के लिए भीड़भाड़ और यात्रियों की असुविधा को दर्शाने वाली पुरानी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। इनमें से कई दृश्य बिना संदर्भ के शेयर किए जा रहे हैं, जिससे जनता को यह भ्रम हो रहा है कि ये हाल ही के हैं। आधिकारिक क्षेत्रीय हैंडल सक्रिय रूप से स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं और ऐसी भ्रामक सामग्री को पुराना और झूठा बता रहे हैं।
पिछले पांच दिनों में, ऐसे 40 से अधिक भ्रामक मामलों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया गया है। भ्रामक सूचना फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए सरकार त्वरित और ठोस कार्रवाई कर रही है।

**त्यौहारी सीजन के दौरान अभूतपूर्व परिचालन**

यात्रियों ने भी इस वर्ष की बेहतर व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से कहीं बेहतर थीं और पूरी यात्रा सुगम और आरामदायक रही।
प्रयागराज, वलसाड, विशाखापत्तनम और संबलपुर स्टेशनों पर यात्रियों ने भारतीय रेल द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया तथा अनारक्षित डिब्बों में भी बेहतर सुविधाओं और प्रबंधन की सराहना की।

**समर्पित कार्यबल एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करता है**

भारतीय रेल ने लेडीज़ सर्कल इंडिया के सहयोग से, आयुष्मान परियोजना के अंतर्गत मैसूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म 2 पर अपनी तरह का पहला नर्सिंग रूम शुरू किया है। यह समर्पित सुविधा माताओं और शिशुओं को एक शांत, स्वच्छ और सुरक्षित स्थान प्रदान करती है, जिससे यात्रा के दौरान उनकी गोपनीयता, सम्मान और आराम सुनिश्चित होता है। वातानुकूलित, अच्छी रोशनी वाला और उच्च स्वच्छता मानकों के अनुरूप, यह नर्सिंग रूम लंबी यात्राओं, देर रात के कनेक्शनों या त्योहारों की भीड़ के दौरान माताओं की जरूरतों को पूरा करता है।
भारतीय रेल की हालिया उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए, लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन उत्तर भारत का पहला पूर्णतः महिला-कर्मचारी स्टेशन बन गया है, जिसने सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के नए मानक स्थापित किए हैं। नियंत्रण कक्ष से लेकर टिकट काउंटर, सुरक्षा गश्ती दल से लेकर सिग्नल केबिन तक, सभी कार्यों का प्रबंधन अब 34 सदस्यीय महिला टीम द्वारा किया जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा शुरू किया गया यह ऐतिहासिक कदम नारी शक्ति की सक्रियता को दर्शाता है, जो यात्रियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और प्रेरणादायक स्थान बनाता है।
चिकित्सा तत्परता और समर्पण का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, पलक्कड़ जंक्शन (दक्षिण रेलवे) के मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. जितिन पी.एस. ने कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस के प्रस्थान से कुछ मिनट पहले प्लेटफ़ॉर्म पर एक 24 वर्षीय यात्री के जबड़े की हड्डी उखड़ने पर उसका उपचार किया। जबड़े की आपातकालीन मैन्युअल कमी को अत्यंत सटीकता से किया गया, जिससे यात्री तुरंत ठीक हो गया और बिना किसी देरी के अपनी यात्रा जारी रख सका। इस त्वरित हस्तक्षेप की सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से सराहना की गई, जिसमें भारतीय रेलवे की चौबीसों घंटे चिकित्सा तत्परता, मौके पर प्रशिक्षित पेशेवरों और प्रमुख स्टेशनों पर आपातकालीन देखभाल के बुनियादी ढांचे को उजागर किया गया।
भारतीय रेल यात्री सुरक्षा, पारदर्शिता और सेवा उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, साथ ही जनता से आग्रह करती है कि वे यात्रा संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए केवल आधिकारिक चैनलों और सत्यापित सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

# बिहार चुनाव में नया समीकरण: पहली बार INDIA और NDA दोनों में सीएम फेस गायब, महागठबंधन में गहराया अंतर्विरोध, रिकॉर्ड 254 प्रत्याशी मैदान में

**(जीएनएस)।** पटना। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होता जा रहा है — न केवल राजनीतिक रणनीतियों के लिहाज से, बल्कि सत्ता समीकरणों की अनिश्चितता के कारण भी। पहली बार ऐसा हुआ है कि न तो सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने और न ही विपक्षी INDIA गठबंधन (महागठबंधन) ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा की है। यह स्थिति बिहार की राजनीति में अभूतपूर्व मानी जा रही है, जहाँ हर चुनाव में किसी एक चेहरे के इर्द-गिर्द पूरा चुनावी विमर्श केंद्रित रहा है।

चुनाव आयोग के अनुसार, विधानसभा की 243 सीटों में से 121 सीटों पर 6 नवंबर और बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और कुल 1,314 उम्मीदवारों ने मैदान में उतरने का ऐलान किया है। इनमें से 300 से अधिक प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए, जबकि 61 ने स्वेच्छा से अपने पर्चे वापस लिए। दूसरे चरण की उम्मीदवारी की स्थिति 23 अक्टूबर तक पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

INDIA गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान अंतिम समय तक जारी रही। आरजेडी ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म होने से मात्र सात घंटे पहले अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी की — एक ऐसा कदम जिसने अंदरूनी असंतोष को और हवा दी। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस को 61, सीपीआई(एम) को 20, सीपीआई को 9, सीपीएम को 6 और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को 15 सीटें दी गई हैं। परंतु, यह गठबंधन समन्वय की कमी का उदाहरण बन गया है, क्योंकि 12 सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। बिहार की राजनीति में यह पहली बार है जब INDIA और NDA दोनों ने टिकट बंटवारे को लेकर कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दोनों खेमों में सीटों की घोषणा अंत तक खिंचती रही और उम्मीदवारों की सूची आखिरी पलों में सामने आई। यह राजनीतिक असमंजस यह संकेत देता है कि दोनों गठबंधन अंदरूनी शक्ति-संतुलन और भविष्य की सत्ता-साझेदारी के सवाल पर



एक स्पष्ट रास्ता तय नहीं कर पाए हैं।

इस बार के चुनाव में कुल 74 राजनीतिक दल मैदान में हैं। प्रमुख मुकाबला एनडीए (भाजपा, जेडीयू, एलजेपी–रामविलास, हम, आरएलएम) और महागठबंधन (राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी) के बीच है, लेकिन नई राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी 'जन सुराज' और आम आदमी पार्टी (AAP) भी सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं।

महिलाओं को टिकट देने में आरजेडी सबसे आगे रही है। पार्टी ने 24 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने 5, जेडीयू और भाजपा ने 13-13 और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 6 महिलाओं को टिकट दिए हैं। दिलचस्प यह है कि एनडीए में कई महिला उम्मीदवार किसी न किसी वरिष्ठ नेता की पत्नी या बेटी हैं, जिससे पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट झलकता है। जातीय समीकरण के लिहाज से भी आरजेडी ने इस बार नई रणनीति अपनाई है। पार्टी ने 51 यादव, 19 मुस्लिम, 14 सवर्ण और 11 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। पिछली बार की तुलना में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं, जेडीयू ने मात्र 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यह सामाजिक गणित स्पष्ट रूप से राजद की कोर वोट बैंक राजनीति के साथ-साथ विस्तारवादी रणनीति की ओर इशारा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री चेहरे की अनुपस्थिति इस चुनाव को पूरी तरह 'दल बनाम दल' की लड़ाई में बदल रही है। बिहार में अब यह मुकाबला किसी एक नेता की लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि गठबंधन की विश्वसनीयता, संगठन की पकड़ और स्थानीय उम्मीदवारों की सामाजिक स्वीकार्यता पर टिका है। राजनीति के पुराने खिलाड़ियों के बीच नए गठबंधनों और नये दलों की सक्रियता से यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक चरित्र में एक नई दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। इस बार के मतदान में जनता न केवल सरकार चुनेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि भविष्य की बिहार राजनीति चेहरों की होगी या विचारों की।

## मथुरा में प्रेमानंद महाराज की तबीयत फिर बिगड़ी, शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में कराई विशेष पूजा और आराधना

**(जीएनएस)।** मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रज की पावन भूमि पर श्रद्धा और चिंता का माहौल है। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर बिगड़ गई, जिससे उनके शिष्यों और अनुयायियों में भारी चिंता व्याप्त हो गई। उन्हें पेट में सूजन की शिकायत मिली और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें बिरला मंदिर स्थित पैथोलॉजी सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी जांच की गई। जांच के दौरान किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। डॉक्टरों की निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन जांच के परिणामों के संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली। महाराज की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही उनके शिष्य चिंतित हो उठे। ब्रजवासियों और शिष्यों ने तत्काल बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा और आराधना का आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम में बृजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा सभा की ओर से लगभग आधे घंटे तक गर्भ गृह की देहरी की पूजा अर्चना की गई। पूजा के दौरान राधा नाम का जाप किया गया और बांके बिहारी जी के चरणों में इत्र, स्वास्तिक चिन्ह और अन्य धार्मिक विधियाँ संपन्न कराई गईं।

बांके बिहारी मंदिर के पुजारी दिनेश गोस्वामी ने बताया कि इस मौके पर मंदिर के पदाधिकारी, शिष्य संत महा माधुरी दास और नवल नगरी दास सहित अन्य अनुयायी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह पूजा महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए की गई और इस दौरान बांके बिहारी जी की अर्चना निरंतर चलती रही। पूजा में केली माल के पदों का गायन भी किया गया और विशेष रूप से ब्रज की विभूति प्रेमानंद महाराज की दी हुई शिक्षाओं और मार्गदर्शन का स्मरण किया गया।

पुजारी ने आगे कहा कि संत प्रेमानंद महाराज ब्रज की विभूति हैं, जिन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। उनके स्वस्थ होने की कामना पूरे ब्रजवासियों और अनुयायियों ने की। इस विशेष पूजा के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि संतों की आराधना और ध्यान मात्र धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि समाज और अनुयायियों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है।

प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य स्थिति पर अभी भी चिकित्सकीय निगरानी जारी है और उनके उपचार के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। ब्रजवासियों और शिष्यों ने अपने सामूहिक श्रद्धा और प्रार्थना के माध्यम से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

## गुजरात में अपराध पर लगाम: 8 हजार अपराधियों पर 8 हजार पुलिसकर्मियों की 24 घंटे निगरानी, डीजीपी बोले 'मेंटर प्रोजेक्ट' से घटे संपत्ति अपराध और नशे के केस

**(जीएनएस)।** अहमदाबाद। गुजरात पुलिस ने अपराध की दुनिया में एक अनोखा प्रयोग किया है, जिसका असर अब साफ नजर आने लगा है। राज्य में अपराध और नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए शुरू किए गए "मेंटर प्रोजेक्ट" के तहत अब तक करीब 8 हजार अपराधियों की पहचान की जा चुकी है। इन सभी पर 8 हजार पुलिस कर्मियों की दिन-रात निगरानी रखी जा रही है। यह योजना राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों को पुनः अपराध की राह पर लौटने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

डीजीपी विकास सहाय ने दीपावली के अवसर पर जारी रिपोर्ट में बताया कि मेंटर प्रोजेक्ट 2023 में शुरू किया गया था। इसके तहत संपत्ति संबंधी अपराधों और नारकोटिक्स मामलों में लिप्त अपराधियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई है। सूची में वे आरोपी शामिल हैं जो पिछले पांच वर्षों में चोरी, लूट, घरफोड़, या नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मामलों में पकड़े गए थे। डीजीपी ने बताया कि इन आरोपियों के वर्तमान ठिकानों की जानकारी जुटाकर उन्हें संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भेजा गया है। इसके बाद हर थाना क्षेत्र में ऐसे अपराधियों की निगरानी के लिए




जिम्मेदार पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। डीजीपी सहाय ने कहा, "हर अपराधी के लिए एक पुलिसकर्मी को 'मेंटर' बनाया गया है। यह मेंटर कोई भी हो सकता है — कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई या पीएसआई। उसकी जिम्मेदारी है कि वह आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे, दिन और रात उसकी मूवमेंट की मॉनिटरिंग करे और यदि जरूरी हो तो उसकी काउंसलिंग भी करे ताकि वह अपराध की दुनिया में दोबारा न लौटे।"

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन मेंटर्स को अपराधियों के सामाजिक और आर्थिक हालात पर भी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी आरोपी के सामने आर्थिक या पारिवारिक संकट है तो पुलिस स्थानीय सामाजिक संस्थाओं की मदद से उसका समाधान कराने की कोशिश करती है। इससे अपराधियों के पुनर्वास की संभावना बढ़ती है और अपराध के दोहराव की संभावना घटती है। राज्य पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, मेंटर प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद से संपत्ति संबंधी अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2023 की तुलना में 2024 में ऐसे अपराधों में 22 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही, अपराधों को सुलझाने की दर (डिटेक्शन रेट) भी काफी सुधरी है। डीजीपी सहाय के मुताबिक, "हमने देखा है कि अधिकांश संपत्ति अपराध या नशे से जुड़े अपराध वे लोग करते हैं जो पहले से ऐसे मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब, मेंटरों की सक्रिय निगरानी से ये अपराधी दोबारा अपराध करने से बच रहे हैं।" गुजरात सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भविष्य में और विस्तृत करने की योजना बनाई है। जल्द ही राज्य के सभी जिलों में अपराधियों के डिजिटल प्रोफाइल तैयार किए जाएंगे ताकि उनकी मूवमेंट और गतिविधियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये भी निगरानी रखी जा सके।

अपराध नियंत्रण के इस अनोखे प्रयास को अन्य राज्यों में भी अपनाने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल पुलिसिंग के "सॉफ्ट एप्रोच" मॉडल की एक मिसाल है, जहां अपराधी को सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिसे समाज में वापस लाना संभव है।

## सूरत में दोस्ती का खूनी अंत: बर्थडे पार्टी में न बुलाने पर युवक को चाकू से गोदा, अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग जारी

**(जीएनएस)।** सूरत। गुजरात के सूरत शहर से एक चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने दोस्ती की सीमाओं और आधुनिक युवा मनोवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामूली-सी बात पर, यानी बर्थडे पार्टी में इनवाइट न करने के गुस्से में एक युवक ने अपने ही दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना सूरत के पांडेसरा इलाके की है, जहाँ एक युवक को उसके दोस्तों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की।

यह सनसनीखेज मामला पांडेसरा बमरोली रोड स्थित सहयोग अपार्टमेंट का है। यहाँ रहने वाले प्रियांशु रामशंकर का जन्मदिन 18 अक्टूबर को था। प्रियांशु एक कुरियर कंपनी में नौकरी करता है और अपने दोस्तों के साथ उसने अपने जन्मदिन की छोटी-सी पार्टी रखी थी। लेकिन इसी पार्टी ने उसकी जिंदगी उलट दी — क्योंकि उसने अपने दोस्त हर्षिल को इस सेलिब्रेशन में आमंत्रित नहीं किया था।

पुलिस के अनुसार, पार्टी में बुलावा न मिलने से हर्षिल बेहद नाराज़ हो गया था। पहले तो दोनों के बीच फोन पर बहस हुई, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। अगले ही दिन, यानी 19 अक्टूबर को हर्षिल ने प्रियांशु को फोन करके शाम को मिलने के लिए बुलाया। दोनों की मुलाकात बालाजी नगर से मणिनगर जाने वाले रोड के पास एक सुनसान जगह पर हुई। वहाँ पहुंचते ही दोनों में फिर से कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्दी ही धक्का-मुक्की में बदल गई।

उसी दौरान हर्षिल का भाई किशन और उसका एक और दोस्त कृष्णा भी मौके पर पहुंच गए। तीनों ने मिलकर प्रियांशु पर हमला बोल दिया। उनके पास पहले से छुपाया गया चाकू था। उन्होंने प्रियांशु को कई बार चाकू से गोदा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और प्रियांशु को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज अभी भी जारी है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पांडेसरा पुलिस ने तीनों आरोपियों — हर्षिल, किशन और कृष्णा — के खिलाफ हत्या के प्रयास (IPC की धारा 307) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में घटना की वजह "बर्थडे पार्टी में न बुलाने की नाराजगी" ही सामने आई है, जो आपसी ईर्ष्या और अहंकार की चरम परिणति को दर्शाती है।

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर युवाओं के बीच बढ़ती हिंसा और आक्रोश समाज के लिए चिंताजनक संकेत हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी किशन और कृष्णा फरार हैं और उनकी तलाश जारी है, जबकि हर्षिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

सूरत जैसे व्यस्त और आधुनिक शहर में यह घटना यह याद दिलाती है कि डिजिटल युग में दिखावटी दोस्ती और सोशल स्वीकार्यता की चाह कभी-कभी युवाओं को इतना असंवेदनशील बना देती है कि रिश्ते, तर्क और जीवन — सब क्षणिक क्रोध की भेंट चढ़ जाते हैं। प्रियांशु की हालत गंभीर बनी हुई है, और अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि वह अभी खतरे से बाहर नहीं है।

यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था के लिए, बल्कि समाज की मानसिक स्थिति के लिए भी एक चेतावनी है — कि आज के युवाओं को भावनाओं पर नियंत्रण और असहमति को सहने की क्षमता सिखाने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।

## पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती और मुजफ्फरपुर के बीच अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

**(जीएनएस)।** पश्चिम रेलवे द्वारा छठ पूजा त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-मुजफ्फरपुर के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इस स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

**ट्रेन संख्या 09483/09484 साबरमती-मुजफ्फरपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (8 फेरे)**

ट्रेन संख्या 09483 साबरमती-मुजफ्फरपुर अनारक्षित स्पेशल 22 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन साबरमती से 23.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 07.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09484 मुजफ्फरपुर-साबरमती अनारक्षित स्पेशल 24 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन मुजफ्फरपुर से 10:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 22.00 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन




महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, ईदगाह, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सीवान, छपरा, सोनपुर एवं हाजीपुर स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

## देश के व्यापार इतिहास में नया अध्याय : दिवाली पर 6.05 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री से जगमगाया भारत का बाज़ार

**(जीएनएस)।** नई दिल्ली। इस वर्ष की दीपावली ने भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक नया स्वर्ण अध्याय जोड़ दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की रिसर्च शाखा 'कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी' द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की दीपावली पर देशभर में अभूतपूर्व 6.05 लाख करोड़ रुपये की बिक्री हुई। इसमें 5.40 लाख करोड़ रुपये का वस्तु व्यापार और 65,000 करोड़ रुपये का सेवा व्यापार शामिल रहा। यह आंकड़ा न केवल त्योहारी कारोबार का, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और उपभोक्ता विश्वास का भी प्रतीक बन गया है। यह पहली बार है जब देश के पारंपरिक बाजारों ने आधुनिक रिटेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए 85 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी अपने नाम की। दुकानों, मंडियों, हाटों और छोटे व्यवसायियों के स्टालों पर इस बार जो भीड़ उमड़ी, उसने स्पष्ट संदेश दिया कि देश का ग्राहक अब स्थानीय उत्पादों



की ओर तेजी से लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी दीपावली' अभियान का गहरा असर उपभोक्ता मनोविज्ञान पर देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार, 87 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने भारतीय वस्तुओं को विदेशी उत्पादों की तुलना में प्राथमिकता दी। इससे चीनी सामानों की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट आई, जबकि देश में निर्मित वस्तुओं की बिक्री में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 25 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024 में दीपावली की कुल बिक्री 4.25 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा 6.05 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। सबसे अधिक कारोबार किराना, एफएमसीजी, सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, रेडीमेड परिधान और गिफ्ट आइटम्स के क्षेत्र में दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों ने सामूहिक रूप से त्योहारी बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके साथ ही फर्नीचर, होम डेकोर, मिठाई, पूजा सामग्री, फल–मेवे, और बेकरी उत्पादों की बिक्री ने भी स्थानीय बाजारों में नई ऊर्जा का संचार किया।

त्योहारी अर्थव्यवस्था में केवल वस्तु व्यापार ही नहीं, बल्कि सेवा क्षेत्र ने भी असाधारण प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार, इस बार सेवा व्यापार 65,000 करोड़ तक पहुंचा। होटल, ट्रैवल एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट, टैक्सी सेवा, पैकेजिंग, टेंट–सजावट और डिलीवरी नेटवर्क जैसी सेवाओं में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। छोटे सेवा प्रदाताओं और स्वरोज़गार से जुड़े युवाओं के लिए यह सीजन आर्थिक समृद्धि लेकर आया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जीएसटी दरों में राहत और मूल्य स्थिरता ने उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। 72 प्रतिशत व्यापारियों ने माना कि उनकी अधिक बिक्री का प्रमुख कारण कर दरों में कमी और कर संरचना की पारदर्शिता रही। उपभोक्ताओं ने भी माना कि उन्हें वस्तुओं के दाम स्थिर लगे, जिससे खरीदारी का विश्वास और बढ़ा।

व्यापारी और उपभोक्ता विश्वास सूचकांक (TCI और CCI) भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे — TCI 8.6 और CCI 8.4 रहा, जो पिछले एक दशक में सर्वाधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रुझान भारत की उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में और अधिक मज़बूत करेगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि दीपावली का यह व्यापार न केवल अर्थव्यवस्था को रोशन करने वाला है, बल्कि यह "भावनात्मक अर्थव्यवस्था" का प्रतीक भी है, जहाँ उपभोक्ता अब केवल वस्तु नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र और समाज के साथ जुड़ाव का अनुभव खरीद रहा है। भारतीय बाजार के इस उत्सवी पुनर्जागरण ने यह साबित कर दिया है कि जब नीति और भावना साथ चलती हैं, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं, बल्कि वास्तविकता बन जाती है। इस दीपावली भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि "स्थानीय ही वैश्विक है" — और यही भाव आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक यात्रा का पथप्रदर्शक बनेगा।

## त्यौहार सीज़न में वडोदरा मंडल ने की व्यापक व्यवस्था, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों से 30 लाख यात्रियों ने की यात्रा

**(जीएनएस)।** दिवाली और छठ पर यात्रियों विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले निवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। दिवाली और छठ की मौके पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से अभी तक वडोदरा मंडल द्वारा परिचालित नियमित एवं 5 स्पेशल ट्रेनों के जरिये अभी तक 30 लाख से ज्यादा यात्रिओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अपने गंतव्य तक यात्रा की है।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने आज आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि वडोदरा मंडल का यह प्रयास है कि छठ के दौरान यात्रिओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे खुशी खुशी अपने परिवार के साथ त्यौहार मना सके। इसके लिए वडोदरा मंडल द्वारा पांच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसके 70 से ज्यादा ट्रिप नोटिफ़िएड किये जा चुके है। वडोदरा



स्टेशन से यात्रियों की सुविधा के लिए मऊ, कोलकाता और गोरखपुर के लिए आरक्षित ट्रेनें चलायी जा रही है, तो वहीं प्रतापनगर से दो अनारक्षित ट्रेनें कटिहार और जयनगर के लिए चलायी जा रही हैं। यात्रिओं तक स्पेशल ट्रेनों की जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहुचायी जा रही है। स्टेशन पर पर्याप्त जगह पर स्पेशल ट्रेनों की सूची लगाई गई है और इसकी उद्घोषणाएं PA सिस्टम पर लगातार की जा रही है।

श्री भडके ने बताया कि यात्रिओं की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट के विशेष प्रयास किये गए है। इसके लिए वडोदरा स्टेशन पर 350 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है,जहां यात्री ट्रेन आने से पहले आराम कर सकते हैं होल्डिंग एरिया में सीटिंग व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त लाइटिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं दी गई है। मंडल के अंकलेश्वर, भरुच, वडोदरा, छायापुरी और गोधरा में यात्रिओं की सहायता के लिए राउंड द क्लॉक टिकट चेकिंग और रेल सुरक्षा बल के अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गयी है, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो। मंडल कार्यालय में वॉर रूम स्थापित किया गया है, जहाँ उच्च अधिकारिओं द्वारा यात्रिओं की भीड़, उनकी सुरक्षा और स्टेशन पर सुविधाओं की निगरानी की जा रही है।

टिकटिंग एवं यात्री सुरक्षा में किये गए प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने आगे बताया कि यात्री को टिकट लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रतापनगर एवं वडोदरा स्टेशन पर एक्स्ट्रा बुकिंग काउंटर खोले गए हैं। यात्रिओं के लिए टिकटिंग को आसान करते हुए टिकट चेकर द्वारा मोबाइल टिकटिंग की भी व्यवस्था की गयी है। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे द्वारा यात्रा की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान प्रभावी समन्वय बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ड्यूटी के दौरान निर्बाध डिजिटल संचार के लिए वॉकी-टॉकी और बॉडी वॉर्न कैमरा का उपयोग कर रहें हैं।

त्योहार के समय यात्री अपने परिजनों से मिलने रेल सेवाओं को लाभ उठा रहे हैं। पश्चिम रेलवे का वड़ोदरा मंडल की आप सभी से अपील है टिकट खरीद कर यात्रा करें और स्टेशन पर उपलब्ध रेलवे कर्मचारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें। पश्चिम रेलवे छठ पर यात्रिओं के सफर को सुविधाजनक और आरामदायक बनाए के लिए प्रतिबध्द है।

## अमेज़न नदी के किनारे तेल उत्खनन को मिली मंजूरी, पर्यावरणविदों ने जताई गहरी चिंता

**(जीएनएस)।** ब्राजील। विश्व की सबसे विशाल और जैव-विविधता से भरपूर नदी प्रणाली अमेज़न नदी के किनारे अब तेल अन्वेषण का मार्ग खुल गया है। ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास को अमेज़न नदी के मुहाने के पास ड्रिलिंग करने की औपचारिक अनुमति मिल गई है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कुछ ही हफ्तों बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP30) आयोजित होने जा रहा है, जिसमें जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी और पर्यावरणीय संतुलन के मुद्दों पर वैश्विक बहस छिड़ने वाली है।

सोमवार को मिली इस मंजूरी के अनुसार, ड्रिलिंग एफ़ज़ेडए-एम-059 ब्लॉक क्षेत्र में की जाएगी, जो अमापा राज्य के तट से लगभग 175 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह इलाका अमेज़न नदी के मुहाने से सटा हुआ है और पर्यावरणविदों के अनुसार "जैव-विविधता का अत्यंत संवेदनशील बिंदु" माना जाता है। पेट्रोब्रास ने बताया है कि ड्रिलिंग का यह अभियान केवल अन्वेषण के लिए होगा और इसमें तेल उत्पादन शामिल नहीं है। कंपनी का कहना है कि पूरा अभियान पांच महीने तक चलेगा, जिसके बाद तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

खनन की अनुमति ब्राजीलियाई पर्यावरण संस्थान (IBAMA) ने दी है, जो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इस संस्थान ने पिछले वर्ष इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, यह कहते हुए कि कंपनी ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) में पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी। लेकिन इस बार पेट्रोब्रास द्वारा विस्तृत अध्ययन और संशोधित सुरक्षा उपायों की रिपोर्ट पेश करने के बाद अनुमति दी गई।

ब्राजील के ऊर्जा मंत्री अलेक्ज़ांद्रे सिल्वेरा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि "सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ड्रिलिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत, पूर्ण पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ की जाएगी। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए करना होगा।"

हालांकि, इस कदम ने ब्राजील और दुनिया भर में पर्यावरण संगठनों और आदिवासी समूहों के बीच तीव्र विरोध की लहर पैदा कर दी है। ग्रीनपीस, WWF ब्राजील और अमेज़निया फॉर लाइफ जैसे संगठनों ने इस निर्णय को "जंगल के भविष्य पर सीधा खतरा" बताया है। उनका कहना है कि अमेज़न तट और इसके आस-पास का समुद्री क्षेत्र तेज धाराओं, प्रवाल भित्तियों और दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जहां किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा सकती है।

आदिवासी नेताओं ने भी चिंता जताते हुए कहा कि यह क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से उनके पूर्वजों की जीवनधारा रहा है। अमेज़न की पारिस्थितिकी केवल पेड़-पौधों या जानवरों का नहीं, बल्कि मनुष्यों का भी जीवन-आधार है। एक स्थानीय समुदाय प्रतिनिधि ने कहा, "अगर यह ड्रिलिंग शुरू हुई, तो यह केवल पर्यावरण का नहीं, हमारी संस्कृति और अस्तित्व का भी विनाश होगा।"

पिछले जून में ब्राजील सरकार ने अमेज़न क्षेत्र के पास कई भूमि और अपतटीय तेल ब्लॉकों की नीलामी की थी। इन ब्लॉकों को शेवरॉन, एक्सॉनमोबिल, पेट्रोब्रास और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (CNPC) जैसी बड़ी कंपनियों को आवंटित किया गया था। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम संकेत देता है कि दक्षिण अमेरिका के कई देश अब ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज में पारिस्थितिक सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में अमेज़न के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी, अब ऊर्जा क्षेत्र के दबाव में हैं। उनकी सरकार चाहती है कि ब्राजील अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए घरेलू ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाए। लेकिन उनके ही कई पूर्व सहयोगी इस नीति से असहमत हैं और मानते हैं कि जलवायु संकट के इस दौर में अमेज़न क्षेत्र में तेल उत्खनन "विकास नहीं, विनाश" की दिशा में कदम है।